

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 03 मार्च, 2026, समय 1305 (5 मिनट))

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया है।

मुख्यमंत्री ने वाटर सिक्क्योर हरियाणा परियोजना के लिए 5 हजार 715 करोड़ तथा हरियाणा ए आई मिशन के लिए 474 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा। एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभागीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल लागू किए जाएंगे। बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।

1- सी एम - 34 सेकंड

राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 14-15 वर्ष की 3 लाख बेटियों को एचपीवी वैक्सीन देने और प्रत्येक जिला व उपमंडल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव भी किया है।

इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती पर रोजगार सब्सिडी 48,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई है, जिनमें पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में शुरू होगा।

कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। धान छोड़कर दालें, तिलहन व कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 प्रति

एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। देसी कपास प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ की जाएगी। प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणित किसानों को 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक अनुदान मिलेगा। 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता जांच के लिए तीन वर्षीय योजना शुरू होगी। ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, एफपीओ को सुदृढ़ किया जाएगा और बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा बढ़ाया जाएगा। मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी क्षेत्र के लिए भी नई प्रयोगशालाएं, प्रसंस्करण इकाइयां और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का प्रस्ताव भी है। यह कंपनी 5,084 कृषि फीडरों और 7 लाख 12 हजार कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी। साथ ही, सभी सरकारी भवनों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने मेक इन हरियाणा नीति के तहत ब्लॉक आधारित वर्गीकरण समाप्त कर सभी क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी को 11,257 से बढ़ाकर 15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश पर निर्णय लिया जाएगा, जिससे लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जल ही जीवन थीम के तहत यमुना नदी की 313 किमी लंबाई में प्रदूषण समाप्त करने के लिए नया मिशन शुरू करने की घोषणा भी की है।

हरियाणा बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। सत्ता पक्ष और आम लोगों ने बजट की तारीफ की है तो विपक्ष ने इसे आंकड़ों का खेल बताया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी महाविद्यालय बरवाला में अर्थशास्त्र की अध्यापिका अमन ने कहा -

2- अमन -33 सेकंड

भिवानी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजनों ने इसे संतुलित व प्रदेश की बेहतरी वाला बजट बताया। गांव हालुवास के किसानों ने इसे किसान हितैषी बताया। करनाल जिले में लोगों ने आम बजट में अन्य क्षेत्रों के साथ करनाल जिले के विकास को लेकर की गई अहम घोषणाओं का स्वागत किया है।
